नीयत, नीति और नतीजा

योगी सरकार में महिलाओं के लिए खुले आत्मनिर्भरता के नए रास्ते

यूपी में महिला कार्यबल की बढ़ती हिस्सेदारी, 12 से 36 फीसदी के पार पहुंचा सफर

- सुरक्षा से स्वावलंबन और स्वावलंबन से आर्थिक भागीदारी तक, रोजगार व उद्यमिता को बढ़ावा
- स्वयं सहायता समूहों को उत्पादन, विपणन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प व कारोबार से जोड़ा
- 50 हजार से अधिक बैंकिंग सखी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनीं, 48,405 करोड़ का ट्रांजेक्शन



किसी भी प्रदेश की आर्थिक प्रगति का आकलन केवल उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी), औद्योगिक निवेश या रोजगार के आंकड़ों से नहीं होता, बल्कि इस बात से भी होता है कि उसकी आधी आबादी विकास की मुख्यधारा में कितनी भागीदार है। महिलाएं जब घर की चारदीवारी से निकलकर खेतों, कारखानों, दफ्तरों, बाजारों और उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, तभी विकास समावेशी और टिकाऊ बनता है। उत्तर प्रदेश में पिछले साढ़े नौ वर्षों के दौरान महिला कार्यबल की बढ़ती हिस्सेदारी इसी बदलाव की कहानी बयान करती है।

वर्ष 2017 में प्रदेश में महिला कार्यबल की हिस्सेदारी करीब 12 फीसदी थी। महिलाओं की शिक्षा, कौशल, सुरक्षा और रोजगार के अवसरों के बीच कई तरह की बाधाएं थीं। बड़ी आबादी वाला प्रदेश होने के बावजूद महिलाओं की आर्थिक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था। सत्ता में आने पर योगी सरकार ने इस स्थिति को केवल सामाजिक चुनौती नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के अवसर के रूप में देखा। सरकार की सोच स्पष्ट थी कि महिला सशक्तीकरण का अर्थ केवल योजनाओं का लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि महिलाओं को रोजगार देने, रोजगार पैदा करने और आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।

नीयतः महिला को लाभार्थी नहीं, विकास का भागीदार बनाना

योगी सरकार की महिला सशक्तीकरण की रणनीति का आधार तीन महत्वपूर्ण पहलू रहे- सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। सरकार का मानना रहा कि जब तक महिलाओं को सुरक्षित वातावरण नहीं मिलेगा, तब तक उनकी शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता की संभावनाएं विकसित नहीं हो सकतीं। इसी सोच के तहत मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ उन्हें उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं और कानूनी सहायता के प्रति जागरूक करना भी रहा। एंटी रोमियो स्क्वॉड, महिला हेल्पलाइन 1090, 181, महिला पुलिस बीट और थानों में महिला हेल्प डेस्क जैसी व्यवस्थाओं ने सार्वजनिक स्थानों और संस्थानों तक महिलाओं की पहुंच को आसान बनाया। इस सोच के पीछे एक बड़ा आर्थिक दृष्टिकोण भी था। महिला सुरक्षित बाहर निकल सकेगी, तो वह पढ़ाई कर सकेगी, नौकरी कर सकेगी, कारोबार शुरू कर सकेगी और अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकेगी।

नीतिः रोजगार से उद्यमिता तक, अवसरों का विस्तार

महिला कार्यबल की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुआयामी रणनीति अपनाई। इसका एक महत्वपूर्ण आधार ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना रहा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों का विस्तार किया गया। इन समूहों को केवल बचत और ऋण तक सीमित न रखकर उत्पादन, विपणन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और छोटे कारोबार से जोड़ा गया। प्रदेश में एक करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना बड़ी उपलब्धि है। इनके माध्यम से महिलाओं को बैंक ऋण, प्रशिक्षण, बाजार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए गए। इसी क्रम में अगले तीन वर्षों में 28.92 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जून 2026 तक प्रदेश में 18.55 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी थीं।

इस बदलाव में बैंकिंग सखी योजना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांवों में बैंकिंग सेवाओं को घर-घर तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग करिस्पॉन्डेंट के रूप में प्रशिक्षित और नियुक्त किया गया। इससे महिलाओं को गांव में ही रोजगार मिला और ग्रामीण नागरिकों को घर बैठे बैंकिंग सुविधाएं मिलीं। प्रदेश में 50 हजार से अधिक बैंकिंग सखियां इस व्यवस्था का हिस्सा बनकर अब तक 48,405 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन कर चुकी हैं। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना, स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास और विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ ही ओडीओपी (एक जनपद-एक उत्पाद) जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण और विपणन में महिलाओं के लिए अवसर तैयार किए। हस्तशिल्प, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और पारंपरिक उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। महिला पुलिसकर्मियों की बढ़ती संख्या ने न केवल रोजगार के अवसर पैदा किए, बल्कि महिला सुरक्षा के प्रति संस्थागत संवेदनशीलता को भी मजबूत किया। औद्योगिक क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। कारखानों में महिलाओं को रात्रिकालीन पाली में काम करने की अनुमति दी, बशर्ते उनकी लिखित सहमति हो और नियोक्ता सुरक्षा, परिवहन, भोजन तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करें। नवंबर 2025 में लागू संशोधित प्रावधानों के तहत खतरनाक श्रेणी के उद्योगों में भी महिलाओं के काम करने की संभावनाओं का विस्तार किया गया। पहले जहां 12 श्रेणियों में शर्तों के साथ अनुमति थी, वहीं इसे 29 श्रेणियों तक विस्तारित किया गया। इससे महिलाओं के लिए विनिर्माण और औद्योगिक रोजगार के नए रास्ते खुले। उनके कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया गया।

नतीजाः आंकड़ों में दिखने लगा बदलाव

इन प्रयासों का परिणाम महिला कार्यबल की बढ़ती हिस्सेदारी के रूप में सामने आया है, जो वर्ष 2017 में मात्र 12 फीसदी से बढ़कर 36 फीसदी से अधिक हो चुकी है। यह बदलाव बताता है कि प्रदेश की महिलाएं अब अर्थव्यवस्था की गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई-कढ़ाई, डेयरी, कृषि आधारित उद्योगों और स्थानीय उत्पादों के निर्माण से जुड़ रही हैं तो शहरी क्षेत्रों में महिलाएं सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी, उद्योग और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश में 50 फीसदी से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। महिला उद्यमिता को स्थानीय बाजारों, ई-कॉमर्स और बड़े उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सेवाओं, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आधुनिक विनिर्माण और उभरते उद्योगों के अनुरूप महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। नए औद्योगिक पार्कों, आईटी सिटी, डेटा सेंटर, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। कार्यस्थलों पर क्रेच, महिला हॉस्टल, सुरक्षित परिवहन, स्वच्छ शौचालय और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत किया गया है। यूपी में महिला सशक्तीकरण की यह तस्वीर आश्चर्यचकित करने वाली है।

मीडिया सॉल्यूशन इनीसिएटिव

भाजपा : सदर सीट पर टिकट की होड़, 25 से ज्यादा दावेदार

दिल्ली से लखनऊ तक नेता लगा रहे जोर, पूर्व महानगर अध्यक्षों से लेकर संगठन के पदाधिकारी तक मैदान में सक्रिय

अमर उजाला ब्यूरो

झांसी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा में सदर सीट को लेकर टिकट की दावेदारी तेज हो गई है। पार्टी में 25 से अधिक नेता टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इनमें पूर्व महानगर अध्यक्षों से लेकर संगठन के मौजूदा पदाधिकारी तक शामिल हैं। कई नेताओं ने क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने के साथ होर्डिंग और वॉल पेंटिंग के जरिये भी अपनी दावेदारी सार्वजनिक कर दी है। टिकट के दावेदार दिल्ली से लखनऊ तक संगठन के बड़े नेताओं से संपर्क साधे रहे हैं।



झांसी सदर विधानसभा सीट पर पिछले तीन चुनावों में लगातार भाजपा को जीत मिली है। ऐसे में इस सीट पर टिकट को लेकर पार्टी के भीतर हलचल तेज है। मौजूदा विधायक रवि शर्मा के अलावा कई नेता अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे चेहरे भी हैं, जो पहले संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वहीं, वर्तमान में विभिन्न पदों पर कार्यरत पदाधिकारी भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं।

दावेदारों ने अपने-अपने स्तर पर क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी, सामाजिक-धार्मिक आयोजनों में उपस्थिति और जनसंपर्क के जरिये मतदाताओं के बीच अपनी पहचान मजबूत करने की कोशिश हो रही है। पार्टी के भीतर 25 से अधिक नामों की चर्चा है।

आज होगी चुनावी तैयारियों की समीक्षा

भाजपा ने भी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। शनिवार को प्रदेश सह प्रभारी जगदीश भाई पटेल झांसी पहुंचेंगे। वह झांसी क्लस्टर की अहम बैठक लेंगे। इसमें संगठन के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारी, पूर्व जिलाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि और अन्य प्रमुख नेता शामिल होंगे। बैठक में संगठन की सक्रियता और चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।

दावेदारों के नामों पर सर्वे में ली जा रही राय

बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की ओर से सर्वे भी कराया जा रहा है। इसमें मौजूदा विधायकों के साथ प्रमुख दावेदारों के नामों पर आम लोगों की राय ली जा रही है। सर्वे रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंपी जाएगी। इसके बाद विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श कर टिकट पर निर्णय लिया जाएगा।

भाजपा में टिकट मांगने का अधिकार प्रत्येक कार्यकर्ता को है। पार्टी जिसे भी टिकट देती है, सभी कार्यकर्ता उसे जिताने में जुट जाते हैं।
– रामकिशोर साहू, क्षेत्रीय अध्यक्ष, भाजपा

ये खुलकर कर रहे दावेदारी

झांसी सदर सीट से भाजपा के टिकट के लिए कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री मनीष तिवारी, सीए दुर्ग्यश चतुर्वेदी, पूर्व महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप सरावगी, पूर्व अध्यक्ष संजीव शृंगीऋषि और निवर्तमान जिला महामंत्री अमित साहू खुलकर दावेदारी कर रहे हैं। इनके अलावा कई अन्य नेताओं ने भी संगठन स्तर पर टिकट की इच्छा जताई है।

आज पूर्वाह्न 11 से शाम 4 बजे तक बिजली की कटौती

झांसी। बिजनेस प्लान 26-27 के अंतर्गत 33/11 केवी सूती मिल उपकेंद्र से निर्गत 11 केवी थापक बाग फीडर पर शनिवार को शीतल कॉलोनी वाले ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का कार्य प्रस्तावित है।

थापक बाग फीडर रहेगा प्रभावित

इस कार्य के कारण अली वाला ट्रांसफार्मर से नक्टा चोपड़ा तक की विद्युत आपूर्ति थापक बाग रोड पर पूर्वाह्न 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाधित रहेगी। संवाद

रैगिंग : फोरेंसिक जांच की बात से पीछे हटे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य

17 नवंबर को एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक में छात्रों से होगी पूछताछ

अमर उजाला ब्यूरो

झांसी। मेडिकल कॉलेज के सीवी रमन हॉस्टल में रैगिंग की शिकायत के साथ मिली ऑडियो की फोरेंसिक जांच कराने की बात कहने वाले प्राचार्य अब इससे पीछे हट गए हैं। पहले उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर ऑडियो की फोरेंसिक जांच कराने की बात कही थी, लेकिन शुक्रवार तक डीएम कार्यालय को इस संबंध में कोई पत्र नहीं मिला। अब प्राचार्य का कहना है कि 15 नवंबर तक हॉस्टल के विद्यार्थी लौट आएंगे। इसके बाद 17 नवंबर को एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक में उनसे पूछताछ की जाएगी।

मेडिकल कॉलेज के सीवी रमन हॉस्टल में बैच-2026 के छात्रों की रैगिंग की शिकायत ई-मेल के जरिये की गई है। इसमें विद्यार्थियों को अपमानित और प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में महानिदेशक (डीजी) ने जवाब तलब किया तो प्राचार्य ने पत्र लिखकर बताया था कि ल्होहार की वजह से हॉस्टल के छात्र घर चले गए हैं। उनके लौटने के बाद जांच कर रिपोर्ट भेजी जाएगी।

इसके बाद प्राचार्य डॉ. सुधीर कुमार ने शिकायत के साथ मिली ऑडियो की फोरेंसिक जांच कराने की बात कही थी। इसके लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखने की बात भी कही गई थी। हालांकि, शुक्रवार तक डीएम कार्यालय को इस संबंध में कोई पत्र नहीं मिला। देर शाम प्राचार्य ने बताया कि 15 नवंबर तक हॉस्टल के विद्यार्थी लौट आएंगे। 17 नवंबर को एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक होगी। इसमें प्रत्येक छात्र से रैगिंग के संबंध में पूछताछ की जाएगी। बैठक में प्रशासन के अधिकारी भी शामिल होंगे। इसी बैठक में आगे की कार्रवाई की रणनीति तय की जाएगी। इसके बाद महानिदेशक को जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी।

37 अनारक्षित ट्रेनों में एक दिसंबर से शुरू होगी कैटरिंग की सुविधा

रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया पैक्ड और शील्ड मिलेगा फूड

अमर उजाला ब्यूरो

झांसी। रेल मंडल से चलने वाली 37 अनारक्षित ट्रेनों (मेमू) में एक दिसंबर से कैटरिंग व्यवस्था शुरू होने जा रही है। इसके तहत ठेका लेने वाली फर्म रेलवे से तय दरों पर पैक्ड और शील्ड खान-पान की बिक्री करेगी।

झांसी मंडल के विभिन्न स्टेशनों से मेमू ट्रेनों का संचालन होता है। इनसे रोजाना हजारों यात्री आवागमन करते हैं। अब तक इन ट्रेनों में अवैध वेंडर ही चाय-पानी, नाश्ता आदि की बिक्री करते हैं। जिससे लोगों की सेहत से खिलवाड़ की आशंका बनी रहती है।

इन पर अंकुश लगाने के लिए मंडल प्रशासन ने अधिकृत कैटरिंग की व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है। यह व्यवस्था एक दिसंबर से चालू हो जाएगी। इन मेमू ट्रेनों में खानपान की बिक्री पैक्ड व शील्ड पैक्ड होगी। सीनियर डीसीएम अमन वर्मा ने बताया एक दिसंबर से 37 ट्रेनों में कैटरिंग व्यवस्था शुरू होगी।

इन ट्रेनों में होगी व्यवस्था शुरू

: ट्रेन संख्या 64613 झांसी-बांदा, ट्रेन संख्या 64611 झांसी-मानिकपुर, ट्रेन संख्या 64616 झांसी-ललितपुर, ट्रेन संख्या 64607 झांसी-कानपुर, ट्रेन संख्या 11807 झांसी-आगरा, ट्रेन संख्या 64615 ललितपुर-झांसी, ट्रेन संख्या 64618 ललितपुर-बीना, ट्रेन संख्या 64639 ग्वालियर-बीकापुर, ट्रेन संख्या 64635 ग्वालियर-बीकापुर में सुविधा शुरू होगी। वहीं, ट्रेन संख्या 64637 ग्वालियर-बीकापुर, ट्रेन संख्या 64641 ग्वालियर-इटावा, ट्रेन संख्या 64614 बांदा-झांसी, ट्रेन संख्या 64609 खजुराहो-झांसी, ट्रेन संख्या 64610 झांसी-खजुराहो, ट्रेन संख्या 51813 झांसी-लखनऊ, ट्रेन संख्या 64633 ग्वालियर-इटावा, ट्रेन संख्या 64643 ग्वालियर-भिंड, ट्रेन संख्या ग्वालियर-बीना, ट्रेन संख्या 64636 भिंड-ग्वालियर, ट्रेन संख्या 64638 भिंड-ग्वालियर, ट्रेन संख्या 64640 भिंड-ग्वालियर, ट्रेन संख्या 64647 खजुराहो-ललितपुर, ट्रेन संख्या 64645 खजुराहो-चित्रकूट, ट्रेन संख्या 64650 खजुराहो-महोबा, ट्रेन संख्या 64644 भिंड-ग्वालियर, ट्रेन संख्या 64648 ललितपुर-खजुराहो, ट्रेन संख्या 64649 महोबा-खजुराहो, ट्रेन संख्या 51861 एट-कोंच, ट्रेन संख्या 51862 कोंच-एट, ट्रेन संख्या 51863 एट-कोंच, ट्रेन संख्या 51864 कोंच-एट, ट्रेन संख्या 51865 एट-कोंच, ट्रेन संख्या 51866 कोंच-एट, ट्रेन संख्या 51867 एक-कोंच, ट्रेन संख्या 51868 कोंच-एट, ट्रेन संख्या 51869 एट-कोंच, ट्रेन संख्या 51870 कोंच-एट में कैटरिंग होगी।

17 को होगा मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन

झांसी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित कार्यक्रम की तिथियों को संशोधित किया गया है। आयोग की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एकीकृत निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 17 नवंबर को होगा। दावे/आपत्तियां 16 दिसंबर तक ली जाएंगी। उनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा।

निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन चार जनवरी को होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ एडीएम वित्त एवं राजस्व पल्लवी मिश्रा ने बताया कि कि जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में अशुद्ध रूप से दर्ज हैं अथवा अपना पता बदलवाना चाहते हैं, वह फॉर्म-8 भर सकते हैं। उक्त सभी फॉर्म अपने बूथ के बीएलओ/ विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ के पास जमा करा सकते हैं। अथवा ईसीआई नेट मोबाइल एप या https://voters.eci.gov.in वेबसाइट से भी भर सकते हैं। ब्यूरो

233 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती अटकी, शासन खफा

निदेशक ने जल्द चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश कार्रवाई की चेतावनी

अमर उजाला ब्यूरो

झांसी। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 233 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। तय समयसीमा बीतने के बाद भी चयन प्रक्रिया लंबित रहने पर शासन ने नाराजगी जताई है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के निदेशक ने डीपीओ को जल्द चयन प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही बरतने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन ने सितंबर, 2025 में दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके तहत जिलों को निर्धारित समयसीमा में चयन प्रक्रिया पूरी करनी थी। बाद में भी शासन स्तर से कई बार निर्देश दिए गए लेकिन झांसी समेत 29 जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया अधूरी है। निदेशक हर्षिता मथुर की ओर से डीएम को भेजे गए पत्र में झांसी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 233 पदों पर चयन लंबित दर्शाया गया है।

निदेशक ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को चयन प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। तय समय में भर्ती पूरी नहीं होने पर संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती की प्रगति की समीक्षा उच्च स्तर पर नियमित रूप से की जाती है। निर्धारित समयसीमा बीत जाने के बाद भी चयन प्रक्रिया पूरी न होने पर उच्च स्तर पर अत्यधिक असंतोष व्यक्त किया गया है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एक सप्ताह के अंदर चयनित कार्यकर्ताओं की सूची जारी हो जाएगी।
–दिनेश सिंह राजपूत, जिला कार्यक्रम अधिकारी।

एटीएम बूथ को निशाना बनाने वालों को तलाश रही पुलिस

झांसी। न्यायालय परिसर के पास स्थित पीएनबी के एटीएम बूथ में मशीन को निशाना बनाने वाले बदमाशों को पुलिस तलाशने में जुटी है। बैंक प्रबंधक सुनील दत्त ने नवाबाद थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई है।

पुलिस ने न्यायालय परिसर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज जुटाए हैं। सीसीटीवी कैमरों में 10 नवंबर की रात तीन युवक बूथ की ओर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एक युवक बूथ के अंदर जाता नजर आ रहा है। बदमाशों ने बूथ के अंदर जाकर मशीन को तोड़कर कैश निकालने की कोशिश की लेकिन, मशीन के ऊपरी हिस्से को ही वह तोड़ सके। जहां कैश रहता है, उस हिस्से को वह नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसके बाद तीनों आरोपी वहां से निकल गए। शाखा प्रबंधक के मुताबिक बूथ की जांच कराने में उसके भीतर रखा सारा कैश सुरक्षित मिला। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके उनकी तलाश की जा रही है। ब्यूरो

एसएसपी ने परखीं क्वार्टर गार्ड एवं शस्त्रागार की व्यवस्थाएं

झांसी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड के बाद उन्होंने क्वार्टर गार्ड, शस्त्रागार और विभिन्न शाखाओं की व्यवस्थाएं परखीं।

एसएसपी ने शस्त्रागार में रखे शस्त्रों, कारतूसों और अभिलेखों का परीक्षण किया। उन्होंने इनके उचित रखरखाव और अभिलेखों को नियमित रूप से अपडेट रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा परिवहन शाखा, रेडियो शाखा और यूपी-112 सहित अन्य शाखाओं का निरीक्षण किया। वहां उपलब्ध उपकरणों, अभिलेखों और कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

उन्होंने सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, अनुशासन बनाए रखने और कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने और पुलिस रिस्पॉन्स बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस दौरान एएसपी सिमरन सिंह समेत अन्य मौजूद रहे। ब्यूरो

अधिक खबरों के लिए amarujala.com

यू.पी. पोस्टल प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि. Registration No. 56 - 27/08/1915
3, बाजपेयी मार्ग, लालबाग, लखनऊ
सावधि जमा पर @ 7.85% सर्वाधिक ब्याज
0.5% Extra for Senior Citizen
111 वर्षों से भारत सेवारत | भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस प्रदत्त | जमा, बीमा एवं ऋण गारंटी निगम भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत | गोखुलाल एंड, हाईटेक्नोलॉजिकल एवं यू.पी.आई. सेवा जल्द ही उपलब्ध
for more details visit www.uppcbl.com or Contact : 8429000507
सावधि - आगरा, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, झांसी, कानपुर, वाराणसी
पूर्वांचल एवं विस्तारपटल मुख्य शाखा लखनऊ • सर्वे जारी।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक
क्षेत्रीय कार्यालयः झाँसी क्षेत्र भूमितल, नगर निगम बिल्डिंग, ईलाइट चौराहा, जिला–झाँसी–284001 (उ.प्र.)
शाखाः ईलाइट चौराहा शाखा, झाँसी
अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना [परिशिष्ट-IV एवं नियम 6 (2) व 8(6) के प्रावधान देखें]

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6(2) व 8(6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनः निर्माण और प्रवर्तन के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना।
जन साधारण तथा विशेषतः ऋणकर्ताओं, बंधककर्ताओं व गारंटरों को एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि प्रत्यभूतित ऋणदाता के पास रेहन रखी/प्रभारित/गिरवी निम्न उल्लेखित अचल संपत्ति जिसका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा प्रत्यभूतित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गाय है। इसकी बिक्री निम्न निर्दिष्ट बकाया राशि की वसूली हेतु "जैसे है जहां है" "जैसे है जो है" और "जो कुछ वहां है" के आधार पर की जाएगी।
ऋणकर्ताओं/ बंधककर्ताओं/ गारंटरों/ प्रत्यभूतित परिसंपत्ति/ बकाया राशि/ आरक्षित मूल्य/ ई–नीलामी की तिथि व समय, ईएमडी व बोली वृद्धि राशि निम्नानुसार है।

ई–नीलामी की तिथिः 03.12.2026 | ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 02.12.2026 सायं 04.00 बजे तक

क्र. सं.	ऋणियों / जमानतदारों / बंधकदारों का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण ज्ञात अतिक्रमणों सहित, यदि कोई हो	कुल बकाया	1. ई–नीलामी की तिथि 2. ई–नीलामी का समय (प्रारंभ समय से समाप्ति समय तक)	1. बारीक धनराशि/ 2. वृद्धि धनराशि/ 3. बिड बढ़ोतरी राशि	कब्जा की स्थिति (सांकेतिक/ भौतिक)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय
1.	ऋणी एवं बंधककर्ताः श्री सहबान अली पुत्र राजा अली, निवासी 1631/ए/ए बाहर दतिया गेट झाँसी खास, झाँसी शहर, झाँसी 284002 जमानतकर्ताः श्री रमजान अली पुत्र राजा अली, निवासी 1631/1ए सुपर कॉलोनी बाहर दतिया गेट झाँसी 284002	आवासीय मकान स्थित मौजा झांसी खास आबादी अलीगोल, तहसील व जिला झांसी, आराजी संख्या 1932, क्षेत्रफल 446.70 वर्ग फीट, मालिकः श्री सहबान अली पुत्र श्री राजा अली, चौहद्दीः पूर्वः विक्रेता का प्लॉट, पश्चिमः रास्ता 5.79 मीटर, उत्तरः सईद का प्लॉट, दक्षिणः रास्ता 3.66 मीटर	रु. 27,33,777.99 + दिनांक 09.11.2026 से संविदात्मक दर पर मासिक किस्तों के साथ ब्याज एवं मुगतान की तिथि तक लागत, शुल्क एवं खर्च सहित	ई–नीलामी की तिथिः 03.12.2026 ई–नीलामी का समयः दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक	1. रु0 12,25,000/- (बारीक मूल्य) 2. रु0 1,22,500/- (अंकित धनराशि) 3. रु0 30,000/- (न्यूनतम बिड बढ़ोतरी राशि)	सांकेतिक कब्जा	01.12.2026 प्रारंभ समयः शाम 3:00 बजे से समाप्ति समयः शाम 5:00 बजे

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/e-auction एवं Baanknet.com पर जाएं। इच्छुक बोलीदाता अधिकृत अधिकारी से मोबाइल नंबर 9519857733 पर संपर्क कर सकते हैं।
दिनांकः 12.11.2026 स्थानः झांसी
हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

अपना अखबार बुक करें ☎ 1800 121 1166

